

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं का नाम

16/11/2007

18-9-14

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस के अवस्थी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रुक्मी प्रमिष्ठ शर्मा उपस्थित उभयपक्षों को प्रकरण का ग्रहण पर पुना गया । इस प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह बयान दे दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने रिब्यू की अनुमति नहीं गई हो जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2000 आर0एन0 76 (उच्च न्यायालय) एवं 2007 आर0एन0 77 का उल्लेख दिया गया है । उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अवैधानिक तरीके से कार्यवाही की जा रही है । उक्त आधार पर उन्होंने निगरानी ग्राह्य करने तथा स्थगन दिए जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि एस.डी.ओ द्वारा दी गई अनुमति के बावजूद आवेदक विचारण न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं इस कारण इस निगरानी का अब कोई औचित्य नहीं है और निगरानी अग्राह्य की जाये ।

2- उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है वह विधिसम्मत है या नहीं । आलोच्य आदेश पत्रिका दिनांक 4-9-14 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने

सिकारों एवं अभि
आदि के हस्ताक्षर

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0.3168-तीन/14

जिला - ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही का क्रमांक	पक्षकार एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
------------------	----------------------	---------------------------------

तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व क तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.9.98 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करने आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुमति अनुविभागीय अधिकारी ने प्रभावित पक्ष को सुने बिना प्रदान की गई है जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। न्यायदृष्टांत 2000 अना-रन-76 में माननीय उच्च न्यायालय में यह सिद्धांत स्थापित करा गया है कि राजस्व मंडल या अन्य सरकारी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाने से पूर्व प्रतिपक्ष को सूचनापत्र देना अनिवार्य है। सुनवाई का समुचित अवसर देना अनिवार्य आवश्यक है। उक्त व्यवस्था न्यायदृष्टांत 2000 अना-रन-76 के द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान अध्यक्ष द्वारा दी गई है। उक्त प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिपक्ष (आवेदक) को सूचना एवं सुनवाई का आदेश दिए बिना अनुमति प्रदान की गई है जो उक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं है। चूंकि इस निगरानी में उक्त को बिना विचारणीय नहीं है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को उक्त आदेश इसी स्तर पर निरस्त कर दिया जाये तथा प्रकरण रद्द। इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन की अनुमति देना जाने हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आवेदक को सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देकर अनुमति के संबंध में विधिवत कार्यवाही उपरोक्त निर्देश के अनुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है।


सूचना

17-7-14
18-9-14

प्रकरण क्रमांक :

12018 निगणपत्ती

शु. भावना पुत्री मदनलाल अग्रवाल,
निवासिन- रुवा नरवर, तहसील नरवा,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

विराट

- मध्यप्रदेश शासन
- तरकिन जैन एवं सगुन कद जैन,
निवासी - वार्ड नम्बर-१०, नरवर,
तहसील नरवर, जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश

पुनर्विचार